

MOST IMMEDIATE
TIME BOUND

No.AV-24012/19/2015-AAI
Government of India
Ministry of Civil Aviation

'B' Block,
Rajiv Gandhi Bhawan,
New Delhi.

Dated: 07.10.2016

To

1. The Registrar General, Supreme Court of India, New Delhi.
2. The Registrar of all High Courts.
3. Chief Secretaries, State Governments/ Administrators of Union territories
4. Secretaries, All Central Ministries

Subject: Filling up the post of Chairperson in the Airports Appellate Tribunal to adjudicate disputes arising due to eviction of unauthorized occupants at airport premises.

Sir/Madam

I am directed to state that in terms of sub-section (1) and (2) of section 28 I of the Airports Authority of India Act, 1994, the Central Government by notification in the official Gazette established a Tribunal known as the Airport Appellate Tribunal w.e.f. 25th March, 2010. The Tribunal consists of a Chairperson and it adjudicates disputes arising out of eviction of unauthorized occupation at airport premises.

2. The qualification and the method of appointment of the Chairperson have been listed in Section 28-I of the said Act and also indicated in the attached Vacancy Circular.

The post carries a pay of Rs. 80, 000/- p.m. (fixed pre-revised) and the service conditions are governed by the AAT (Salary, Allowances and other terms and conditions of service of Chairperson), Rules 2004 (copy enclosed).

It is, therefore, requested to recommend the names of eligible persons for appointment to the above post along with particulars of the candidates, CR Dossier of last years and vigilance clearance, in the attached proforma, latest by the 20th November, 2016.

Yours faithfully,

Venkataramana R. Hegde
(Venkataramana R. Hegde)
Director
Tel: 24610366

Encl. As above.

Copy to: SO (IT) for uploading in the website of MoCA.

VACANCY CIRCULAR

In terms of sub-section (1) and (2) of section 28 I of the Airports Authority of India Act, 1994, the Central Government had by notification in the official Gazette established a Tribunal known as the Airport Appellate Tribunal w.e.f. 25th March, 2010. The Tribunal consists of a Chairperson and it adjudicates disputes arising out of eviction of unauthorized occupation at airport premises.

The qualification for the post of Chairperson as prescribed in clause 5 of ~~the Sub-Section (1) of Section 28-I~~ of the Airports Authority of India [Amendment Act, 2003] is as under.

~~"A person shall not be qualified for appointment as Chairperson of the Tribunal unless he is, or has been, or is qualified to be, a Judge of a High court".~~

3. The post carries a pay of Rs. 80, 000/- p.m. (fixed pre-revised) and the service conditions are governed by the Airport Appellate Tribunal (salary, allowances of other terms and conditions of service of Chairperson), Rules 2004 (AAT Rules).

4. The Chairperson of the Tribunal shall hold office as such for a term of three years from the date on which he enters upon his office or until he attained the age of 62 years, whichever is earlier.

5. Particulars of the candidates recommended may be sent along with CR dossier and Vigilance Clearance in the attached proforma, latest by the 20th November, 2016 to Shri Venkataramana R. Hegde, Director, Ministry of Civil Aviation, 'B' Block, Rajiv Gandhi Bhawan, Safdarjung Airport, New Delhi - 110 003. Ministries/Departments of Central/State Governments, Union Territory Administrations may also recommend suitable candidates serving in the PSUs/Corporations etc.

6. As per Section 11 of the AAT Rules, the person appointed as Chairperson shall be eligible, subject to availability, to the use of official residence for the General Pool accommodation. However, in the past, accommodation from the GS pool could not be made available for the Chairperson. Therefore, the selected person will be entitled for HRA as admissible.

7. This vacancy circular, application form are also placed on this Ministry's website: www.civilaviation.gov.in for easy accessibility.

Application format for the post of ~~Chairman~~ in the Airport Appellate Tribunal.

i.	Name of the Post applied for	:	
ii.	Name of the Applicant	:	
iii.	Father's Name	:	
iv.	Date of Birth	:	
v.	Age as on 01.10.2016	:	
vi.	Address for communication	:	
vii.	Telephone No. i) Landline with STD Code ii) Mobile	:	
viii.	E-mail Address	:	
ix.	Educational/Professional Qualification	:	
x.	Experience	:	
xi.	Full employment record in chronological order	:	

Declaration:

The Information furnished above is true and correct to the best of my knowledge and belief.

(Signature of Applicant)

- (b) the nature, size and standard of the accommodation available in such premises;
- (c) the rent that would have been realized if the premises had been let on rent for the periods of unauthorized occupation to a person who is not in the service of the airport;
- (d) any damages done to the premises during the period of unauthorized occupation;
- (e) any other matter relevant for the purpose of assessing the damages.

(2) The eviction officer who makes an order under sub-section (1) or sub-section (2) of section 28G of the Act may direct that the arrears of rent or the damage assessed under sub-rule (1) shall be payable together with simple interest at the rate not exceeding twelve per cent per annum.

[No. AV-20036/102/2003-AAI]

Dr. NASIM ZAIDI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर, 2004

का०आ० 1126(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 (1994 का 55) की धारा-41 की उप-धारा (2) के खण्ड (छ vi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1):— इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत और सेवा के अन्य निबंधन और सव्यो नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं:- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

- (क) अधिनियम से अभिप्रेत है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 (1994 का 55);
- (ख) अध्यक्ष से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 28 झ की उपधारा (4) है अधीन अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त व्यक्ति;

(ग) अधिकरण से अधिनियम 28 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित नियुक्ति के अधिनियम

(घ) अन्य सभी शर्तों और शर्तों के अधिनियम 28 की उपधारा (1) के अधिनियम में प्रयुक्त किया गया है किन्तु पारिभाषिक नहीं किया गया है, परन्तु जो अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो अधिनियम में क्रमशः उनका है।

3. वेतन:- अध्यक्ष को उतना ही वेतन मिलेगा जितना कि एक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को अनुज्ञेय है।

परन्तु यदि अध्यक्ष के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है जो कि उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हो चुका है तथा जिसे पेंशन, उपदान, अंशदायी भविष्य निधि में नियोजक के अंशदान या अन्य सेवानिवृत्ति फायदे या तो प्राप्त हो चुके हैं या प्राप्त हो रहे हैं या वह इन फायदों को प्राप्त करने का हकदार हो चुका है, ऐसे अध्यक्ष के वेतन उसके द्वारा प्राप्त किए गए या प्राप्त किए जाने वाले अंशदायी भविष्य निधि में नियोजक का अंशदान या पेंशन की कुल राशि या किसी अन्य प्रकार के सेवानिवृत्ति फायदे, यदि कोई है, को घटा दिया जाएगा।

4. महंगाई भत्ता और नगर प्रतिकारात्मक भत्ता:- अध्यक्ष उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अनुज्ञेय दर पर महंगाई भत्ता और नगर प्रतिकारात्मक भत्ता पाने का हकदार होगा।

5. छुट्टी:- कोई व्यक्ति, अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति पर निम्नानुसार छुट्टी का हकदार होगा:-

(i) सेवा के प्रत्येक पूर्ण कैलेण्डर वर्ष अथवा उसके भाग के लिए तीस दिन की दर पर अर्जित अवकाश,

परन्तु यह कि छुट्टी खाते में अर्जित छुट्टी अग्रिम रूप में, प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के जनवरी तथा जुलाई मास के प्रत्येक पहले पन्द्रह दिन की किश्तों में, जमा कर दी जाएगी;

परन्तु यह और यह कि इस प्रकार अग्रणीत की गई छुट्टी तथा आधे वर्ष के लिए, नाम में डाली गयी छुट्टी मिलकर एक सौ अस्सी दिन की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं बैठती हों, इसके अधीन रहते हुए छुट्टी खाते में पूर्ववर्ती आधे वर्ष की समाप्ति के साथ अगले आधे वर्ष में अग्रणीत करके जमा कर दी जाएगी,

—5—

(ii) सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए बीस दिनों की दर पर चिकित्सा प्रमाण-पत्र अथवा निजी कारणों पर अर्ध वेतन छुट्टी तथा अर्ध वेतन छुट्टी के लिए छुट्टी वेतन अर्जित छुट्टी के दौरान अनुज्ञेय वेतन छुट्टी के आधे के बराबर होगा;

(iii) आधे वेतन पर छुट्टी को भारत के राष्ट्रपति के विवेकाधिकार से पूर्ण वेतन छुट्टी में परिवर्तित किया जा सकेगा, बशर्ते वह चिकित्सीय आधार पर ली गयी है तथा इसके वर्णन में एक सख्त चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा प्रमाणपत्र लगाया गया हो.

(iv) एक कार्यकाल में अधिकतम एक सौ अस्सी दिनों की अवधि तक अवैतनिक असाधारण छुट्टी तथा भत्ते।

6. छुट्टी मंजूरी प्राधिकारी:- भारत के राष्ट्रपति अध्यक्ष की छुट्टी स्वीकृत करने के लिए सख्त प्राधिकारी होंगे।

7. पेंशन भविष्य निधि:- यदि कोई सेवारत न्यायाधीश अध्यक्ष के पद को धारण कर रहे हैं तो ऐसे मामले में ली जाने वाली पेंशन के लिए गणना उसी सेवा के नियमों के अनुसार होगी जिससे वह जुड़ा हुआ है। वह साधारण भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियम, 1960 के उपबंधों द्वारा भी शासित होगा। अन्य सभी मामलों में, व्यक्ति अंशदायी भविष्य निधि (भारत) नियम, 1962 का हकदार होगा।

8. यात्रा भत्ता:- दौरे या स्थानांतरण (जिनमें अधिकरण में पद ग्रहण करने के लिए अध्यक्ष अधिकरण में अपने कार्यकाल की सम्पत्ति पर अपने गृह नगर के लिए की गई यात्रा-सम्मिल है) के समय अध्यक्ष उच्च न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ता) नियम, 1956 के उपबंध के अधीन उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के लागू मानों एवं दरों पर ही यात्रा भत्ता, दैनिक भत्तों, निजी असबाब की दुलाई तथा अन्य ऐसे ही मामलों के लिए हकदार होगा।

9. छुट्टी यात्रा रियायत:- अध्यक्ष उन्हीं दरों और उन्हीं मानों पर छुट्टी यात्रा रियायत का हकदार होगा जैसा कि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को लागू हैं।

10. वाहन की सुविधा:- अध्यक्ष स्टाफ कार तथा प्रति मास एक सौ पचास लिटर पेट्रोल अथवा प्रतिमास वास्तविक रूप से उपभोग किए गए पेट्रोल, जो भी कम हो, के लिए हकदार होगा।

11. आवास:- (1) अध्यक्ष के लिये निम्न प्रत्येक व्यक्ति साधारण पूल से शासकीय निवास के उपयोग के लिए केन्द्रीय सरकार के समूह के अधिकारी को अनुज्ञापित है जिसका हकदार होगा, जो कि उस स्थान पर कार्यरत हो जहां ऐसा व्यवस्थापित है जब समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट दरों पर अनुज्ञापित फीस के मुकतान पर समान वेतन प्राप्त कर रहा हो।

(2) जहां अध्यक्ष अनुज्ञेय अवधि से अधिक समय तक सरकारी आवास पर काबिज है, वह अतिरिक्त अनुज्ञापित फीस या शास्तिक किराया, जैसा भी मामला हो, संदाय करने का दायी होगा तथा वह केन्द्रीय सरकार के सेवकों पर लागू नियमों के अनुसार वेदखली का दायी होगा।

(3) जहां अध्यक्ष उप-नियम (1) के अधीन सरकारी आवास की सुविधा नहीं ले रहा है, वहां वह समान वेतन प्राप्त कर रहे केन्द्रीय सरकार के समूह के अधिकारी को अनुज्ञाय गृह किराया भत्ता का हकदार होगा।

12. चिकित्सीय उपचार की सुविधा:- अध्यक्ष, अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना नियम, 1954 में प्रदत्त चिकित्सीय उपचार तथा अस्पताल सुविधाओं का हकदार होगा और उन स्थानों पर जहां केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना प्रचालन में नहीं है, उक्त अध्यक्ष केन्द्रीय सेवाएं चिकित्सा परिचर्या नियम, 1944 में दी गई सुविधाओं का हकदार होगा।

13. अवशिष्ट उपबंध:- अध्यक्ष की सेवाओं की शर्तों से संबंधित वे मामले, जिनके संबंध में इन नियमों में कोई व्यक्त उपबंध नहीं किया गया है, प्रत्येक दशा में केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के निर्दिष्ट किए जाएंगे तथा उन पर केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अध्यक्ष के लिए आबद्धकर होगा।

14. शिथिल करने की शक्ति:- केन्द्रीय सरकार को किसी वर्ग या प्रवर्गों के व्यक्तियों के संबंध में इन में से किसी भी नियम के उपबंधों को शिथिल करने की शक्ति होगी।

[सं० एवी-20036/102/2003-एएआई]

डा० नसीम जैदी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th October, 2004

S.O. 1126(E).—In exercise of the powers conferred by Clause (gvi) of sub-section (2) of Section 41 of the Airports Authority of India Act, 1994 (55 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. The Airports Authority of India (Appellate Tribunal) Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

- (a) "Act" means the Airports Authority of India Act, 1994 (55 of 1994);
- (b) "Chairperson" means a person appointed as Chairperson of the Tribunal under sub-section (4) of section 28-I of the Act;
- (c) "Tribunal" means the Airport Appellate Tribunal established under sub-section (1) of section 28-I of the Act;
- (d) all other words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Salary.—The Chairperson shall be paid such salary as admissible to serving Judge of a High Court.

Provided that in the case of an appointment of a person as a Chairperson, who has retired as a Judge of a High Court who is in receipt of or has received or has become entitled to receive any retirement benefit by way of pension, gratuity, employer's contribution to the Contributory Provident Fund or other forms of retirement benefits, the pay of such Chairperson shall be reduced by the gross amount of pension or employer's contribution to the Contributory Provident fund or any other form of retirement benefit, if any, drawn or to be drawn by him.

4. Dearness allowance and city compensatory allowance.—The Chairperson shall be entitled to draw dearness allowance and city compensatory allowance at the rate admissible to a Judge of a High Court.

5. Leave.—A person, on appointment as the Chairperson shall be entitled to leave as follows, namely:—

- (i) earned leave at the rate of thirty days for every completed calendar year of service of a part thereof.

— 8 —

Provided that the leave account shall be accumulated leave, in advance, in two installments of fifteen days each, on 1st January and July of every calendar year:

Provided further that the leave account shall be credited with the close of previous half year shall be carried forward to the next half year, subject to the condition that the leave so carried forward plus leave earned in the half year do not exceed the maximum limit of one hundred and eighty days.

(ii) half pay leave on medical certificate or on private affairs at the rate of twenty days in respect of each completed year of service and the leave salary for half pay leave shall be equivalent to half of the leave salary admissible during the earned leave;

(iii) leave on half pay may be commuted to full pay leave at the discretion of the President of India. Provided it is taken on medical grounds and is supported by a medical certificate by a competent medical authority;

(iv) extraordinary leave without pay and allowances up to a maximum period of one hundred and eighty days in one term of office.

6. Leave sanctioning authority.- The President of India shall be the authority competent to sanction leave to the Chairperson.

7. Pension/Provident Fund.- In case a serving Judge is holding the post of Chairperson shall count for pension to be drawn in accordance with the rules of the service to which he belongs. He shall also be governed by the provisions of the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960. In all other cases, a person shall be entitled to Contributory Provident Fund (India) Rules, 1962.

8. Traveling Allowances.-The Chairperson while on tour or on transfer (including the journey undertaken to join the Tribunal or on the expiry of his term with the Tribunal to proceed to his home town) shall be entitled to the traveling allowances, daily allowances, transportation of personal effects and other similar matters at the same scales, and at the same rates as are applicable to a judge of High Court under the provision of the High Court Judge (Traveling Allowances) Rules, 1956.

9. Leave Travel Concession.- ~~The Chairperson shall be entitled to leave travel concession at the same rates and at the same scale as are applicable to a Judge of a High Court.~~

10. Facility of conveyance.- The Chairperson shall be entitled to a staff car and one hundred and fifty litres of petrol every month or actual consumption of petrol per month, whichever is less.

11. Accommodation.- (1) Every person appointed as the Chairperson shall be eligible subject to availability to the use of official residence from the general pool accommodation of the type admissible to a Group 'A' officer of the Central Government, who is working at the place where such tribunal is located and drawing an equivalent pay on payment of the licence fee at the rates specified by the Central Government from time to time.

(2) Where the Chairperson occupies an official residence beyond permissible period, he shall be liable to pay additional licence fee or penal rent, as the case may be, and he shall be liable to eviction in accordance with the rules applicable to Central Government servants.

(3) Where the Chairperson does not avail of facility of official residence under sub-rule (1), he shall be entitled to House Rent Allowance as admissible to Group 'A' officers of the Central Government, drawing equivalent pay.

12. Facilities for medical treatment. The Chairperson shall be entitled to medical treatment and hospital facilities as provided in the Contributory Health Services Scheme Rules, 1954 and in places where the Central Health Services Scheme is not in operation, the said Chairperson shall be entitled to the facilities as provided in the Central Services medical Attendance Rules, 1944.

13. Residuary provision. Matters relating to the conditions of services of the Chairperson with respect to which no express provision has been made in these rules shall be referred in each case to the Central Government for its decision and the decision of the Central Government thereon shall be binding on the said Chairperson.

14. Power to relax. The Central Government shall have power to relax the provisions of any of these rules in respect of any class or categories of persons.

[No. AV-20036/102/2003-AAI]

Dr. NASIM ZAIDI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर, 2004

का.अ.सं. 1127(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 (1994 का 55) की धारा 28 की उप-धारा (3) के साथ प्रतिष्ठित धारा 41 की उप-धारा (2) के खण्ड (छ vi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1):— इन नियमों का संक्षिप्त नाम विमानपत्तन अपील अधिकरण (अध्यक्ष के कदाचार अथवा उनकी अक्षमता के अन्वेषण के लिए प्रक्रिया) नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं:— इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

(क) अधिनियम से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 (1994 का 15) अभिप्रेत है,

(ख) अध्यक्ष से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 28 झ की उपधारा (4) के अधीन अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त व्यक्ति;

(ग) अधिकरण से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 28 झ के उपधारा (1) के अधीन विमानपत्तन अपील अधिकरण;